उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(07/60)**

दिनांक 11 एवं 12 जुलाई, 2017 को सहकारी प्रबन्ध संस्थान, राजपुर रोड, देहरादून में अर्थ एवं संख्या निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा राष्ट्रीय प्रतीदर्श सर्वेक्षण 75वीं आवृत्ति की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ निदेशक अर्थ एवं संख्या श्री सुशील कुमार द्वारा किया गया।

इस अवसर पर निदेशक अर्थ एवं संख्या श्री कुमार ने कहा कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार गत वर्षो की भांति राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे जिसमें सैंपल आधार पर चयनित परिवारों से राज्य में विशेष रुप से उपभोक्ता व्यय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषयों से संबंधित आंकड़े संग्रहित किए जाने हैं। आंकड़े संग्रहण करने की अवधि जुलाई 2017 से जून 2018 तक निर्धारित है। अर्थ एवं संख्या निदेशालय, नियोजन विभाग द्वारा संग्रहित आंकड़ों के परिणामों का उपयोग राज्य एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा देश की समृद्ध अर्थव्यवस्था के नीति निर्धारण हेतु किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनेक अनुसंधान विशेषज्ञों एवं शैक्षिक शोधकर्ताओं द्वारा भी इसका उपयोग किया जाएगा।

प्रशिक्षण में एनएसएसओ क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपनिदेशक श्री बी.सी.नेगी, अपर निदेशक/सचिव सेवा का अधिकार आयोग उत्तराखंड श्री पंकज नैथानी एवं संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या श्री सुंदरलाल तथा समस्त जनपदों मंडलो तथा निदेशालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(07/59)**

निबन्धक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री टीकम सिंह पंवार ने जानकारी दी कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग द्वारा हरेला पर्व में अपने जनपदीय भेषज संघों व भेषज विकास इकाईयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जड़ी–बूटी/औषधीय पौध प्रजातियों यथा–तेजपात, आंवला व रीठा आदि के पौधों का वितरण किया जाएगा। जिसके लिये समस्त संघ सचिवों एवं जिला भेषज समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि, वे संघ नर्सरी में उपलब्ध जड़ी–बूटी/औषधीय पौध प्रजातियों को ''हरेला पर्व'' के अवसर पर नागरिकों एवं सरकारी विभागों के प्रांगण में रोपण हेतु निःशुल्क वितरित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जनपद में नर्सरी न होने या नर्सरी में पौध उपलब्ध न होने की दशा में जिला भेषज समन्वयक के माध्यम से वन विभाग व निकटस्थ भेषज संघ के सचिवों से सम्पर्क कर पौध की मांग करें, यदि उनके द्वारा निःशुल्क पौध उपलब्ध कराया जाता है, तो पौध प्राप्त कर हरेला पर्व में पौध वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि समस्त सचिवों को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि जनपदीय नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में पौध उपलब्ध हो तो उसे उपने निकटस्थ जनपदों की मांग के अनुसार उपलब्ध करायें। वितरित एवं उपलब्ध कराये गये पौधों की सूचना जिला भेषज समन्वयक, भेषज विकास इकाई, मुख्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/58)**

राष्ट्रपति निर्वाचन, 2017 के संबंध में मतदान दिनांक 17 जुलाई, 2017 को कक्ष संख्या–321 द्वितीय तल, विधान सभा भवन, देहरादून में पूर्वाहन 10:00 बजे से सांय 5:00 बजे के बीच होगा।

सचिव, विधानसभा एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर श्री जगदीश चन्द्र ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति निर्वाचन, 2017 के सम्बंध में उत्तराखण्ड विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों एवं संसद सदस्यों, जिन्हे निर्वाचन आयोग ने विशेषतया देहरादून में मत देने के लिए अधिकृत किया हो की सुविधा हेतु मतदान स्थल की उक्त व्यवस्था की गई है।

उन्होने बताया कि उत्तराखण्ड विधान सभा के निर्वाचित सदस्य एवं संसद सदस्य भारत निर्वाचन आयोग से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने के पश्चात निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति के उपरान्त ही किसी भी राज्य मुख्यालय मे स्थित निर्वाचन स्थल अथवा संसद भवन कक्ष संख्या–62 नई दिल्ली में भी सुविधा प्राप्त कर सकते है। एतदर्थ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश एवं निर्धारित प्रारूप माननीय समस्त निर्वाचकगणों को प्रेषित की जा चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन मतदान स्थल पर मोबाइल फोन, कार्डलैस फोन, वायरलैस सैट तथा कैमरा आदि लाना निषेध है।

उन्होने बताया कि निर्वाचकगण देहरादून स्थित विधानसभा भवन के द्वितीय तल में अपना परिचय–पत्र दिखाकर मतदेय कक्ष में प्रवेश करेंगे तथा मतदान करने के उपरान्त मतदान कक्ष से बाहर निकल जायेंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(07/57)**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने मुजफ्फरनगर–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की जानकारी दी। फोर लेनिंग के कार्य में 67 प्रतिशत भौतिक प्रगति की है। मार्च 2018 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। एत्मालपुर, बहेड़ी, राजपूताना और बिझौली गांव में कार्य रुका हुआ था। प्रशासनिक हस्तक्षेप से इन गांव का कार्य भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने हरिद्वार और देहरादून में मिट्टी, आरबीएम, कांक्रीट मिक्सिंग प्लांट की अनुमति दे दी है। हॉट मिक्स प्लांट लगाने के लिए सितंबर से दिसंबर तक की अनुमति दे दी जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि मंगलोर में मस्जिद शिफ्ट कर अन्य स्थान पर बनाने के लिए 36 लाख रुपए दे दिए गए हैं। जमीन की तलाश कर ली गई है। जमीन के लिए 6 लाख रुपये जल्द मस्जिद समिति को दे दिए जाएगा। इसी तरह से बहेड़ी में भी मस्जिद शिफ्ट करने के लिए 38.17 लाख रुपए दे दिए गए हैं। मस्जिद समिति द्वारा नये चिन्हित स्थानों पर जल्द मस्जिद निर्माण का कार्य शुरु कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 1563 करोड़ रुपए की लागत से 80 किमी मुजफ्फरनगर–हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेनिंग का कार्य चल रहा है। इसके लिए फोर 479.70 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवासीय योजना के प्रगति की जानकारी दी। बताया कि राज्य में है एएचपी (एफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट), बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कांस्ट्रक्शन) और आईएसएसआर (इन–सीटू स्लप रीडेवलपमेंट) के अंतर्गत 75,000 आवश्यक की मांग है। इसमें 25000 सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम) के तहत आवासों की मांग शामिल नहीं है। आवासों की मांग का का सत्यापन कर लिया गया है। वर्ष 2020 तक 70000 आवासों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2017–18 में 18000, 2018–19 में 26000 और 2019–20 में 26000 आवासों का निर्माण किया जाएगा। बीएलसी के तहत 5000 आवासों का निर्माण इस वर्ष कर लिया जाएगा। बताया कि भारत सरकार द्वारा बताए गए 05 सुधारों में 03 सुधार कर लिए गए हैं। सिर्फ दो सुधार एक माह में पूरे कर लिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचिव आवास अमित नेगी, सचिव राजस्व हरबंस सिंह चुघ, प्रभारी सचिव शहरी विकास राधिका झा, निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे, अपर सचिव आवास विनोद सुमन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वीरेन्द्र सिंह, मीडिया प्रभारी : 7055007014

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(07/56)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में इंडो यूरोपियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इटली के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर जॉन मार्टिन थॉमस के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र तथा इटालियन डेलीगेशन के बीच राज्य में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों नवीकरणीय ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक बसो के परिचालन, पोस्ट हार्वेस्ट इन्वेस्टमेंट, कलस्टर डेवलपमेंट, राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करवाने, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक विकास ऊर्जा उत्पादन की संभावनाए तथा लिथियम बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं आदि पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में क्लस्टर फार्मिंग को प्रोत्साहित करना चाहती है। राज्य के प्रत्येक घर में 2019 शत प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करवानी है। इस दिशा में दूरुस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक उपकरण सहायक हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक विकास तथा ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। सिडकुल द्वारा सौर पार्कों के विकास की योजना बनाई गई है। विश्व भर में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का क्षेत्र एक केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है और उत्तराखंड राज्य में भी लिथियम बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य में फलों के प्रसंस्करण द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सकता है। राज्य के किसान बहुत परिश्रमी है यदि उन्हें पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए तो किसान व्यवसायिक रूप से भी सफल रहेंगे।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 12 जुलाई, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(07/55)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में द काउंसिल जनरल ऑफ कनाडा इन चंडीगढ़ श्री क्रिस्टोफर गिबिन ने भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र तथा श्री क्रिस्टोफर गिबिन के मध्य मुख्यत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम लगाने, यूजेवीएनएल के पावर प्रोजेक्टस की क्षमता विकास हेतु आधुनिकीकरण में फंडिंग एवं सलाहकारी सेवाएं देने, छिबरौ तथा खोदरी पावर प्रोजेक्टस के एकीकरण, राज्य के 13 नए पर्यटन स्थल विकसित करने तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अवस्थापना सुविधाओं के प्रबन्धन व विकास में कनाडा की बेस्ट प्रैक्टिसेज का उपयोग आदि पर चर्चा हुई।

बैठक में चर्चा की गई कि कनाडा की पर्यटन विकास क्षेत्र में ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज जो उत्तराखंड के अनुकूल हो का राज्य में नए पर्यटन स्थल विकसित करने में उपयोग किया जा सकता है। कौशल विकास के क्षेत्र में कनाडा की स्किल डेवलपमेंट में विशेषज्ञ कम्युनिटी कॉलेज का राज्य की शिक्षण संस्थानों व आई0टी0आई0 आदि से एमओयू पर विचार किया गया।

श्री क्रिस्टोफर गिबिन द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेतु तकनीकी तथा विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने मे रुचि दिखाई गई। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में कनाडा द्वारा ऑर्गेनिक, हर्बल फार्मिंग तथा फलों के उत्पादन एवं प्रोसेसिन्ग में विशेषज्ञ सेवाएं देने हेतु एमओयू पर विचार किया गया।

बैठक में मुख्य सचिव श्री एस रामास्वामी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री ओमप्रकाश, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।